भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1964
दिनांक 11 दिसंबर 2025

पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण

1964. श्री अरुण गोविलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में कच्चे तेल की मांग का 85 प्रतिशत तक आयात करती है और क्या सरकार उक्त उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने हेतु सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे विभिन्न सम्मिश्रण विकल्पों पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से विदेशी मुद्रा की बचत, पर्यावरण में सुधार और गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का समय पर भुगतान के रूप में लाभ प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्तमान में पेट्रोल में कितनी मात्रा में इथेनॉल मिलाया जा रहा है; और
(ङ) इसके फलस्वरुप देश को कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) चालू वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) में देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता का प्रतिशत 88.5% है। सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, घरेलू कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए और मिश्रण विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता को एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी-वन योजना, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आदि के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार के पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी प्रयासों का समर्थन हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल द्वारा किया जाता है। सरकार, विदेशी विनिमय की बचत करते हुए कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने तथा घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति- 2018, वर्ष 2022 में यथा-संशोधित में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले ईएसवाई 2025-26 कर दिया है। भारत पहले ही ईएसवाई 2024-25 के दौरान 19% से अधिक के मिश्रण को प्राप्त कर चुका है।

सरकार ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव-ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल, अवशेष निवारण) योजना को अधिसूचित किया जिसका उद्देश्य देश में लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके उन्नत जैव-ईंधन परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, सरकार ने विमानन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने की दिशा में वर्ष 2027 में 1% के सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) के सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य (शुरुआत में अंतरर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए) को मंजूरी प्रदान की।

सरकार ने सीबीजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी), बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (बीएएम) की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में सीबीजी के परिवहन के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे (डीपीआई) के विकास की योजना जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

सरकार ने एलपीजी तथा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के उपयोग को स्वच्छ घरेलू खाना बनाने संबंधी ईंधन के रूप में प्रोत्साहित किया है। मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए की गई थी। ओएमसीज, पर्यावरण की दृष्टि से खाना बनाने संबंधित किसी संधारणीय समाधान को विकसित करने के उद्देश्य से भी नए समाधानों पर कार्य भी कर रही हैं तथा स्टार्टअप्स को एथेनॉल एवं सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टोव जैसे अत्याधुनिक समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

सरकार, भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युतपन्नों कों के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का क्रियान्वयन कर रही है। हरित हाइड्रोजन बदलाव हेतु कार्यनीतिक उपाय ही इस मिशन का एक प्रमुख घटक है जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

देश के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का हिस्सा 2014-15 के 17.20% से बढ़कर 2024-25 के 22.06% हो गया है। इसके अलावा, मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान, देश के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का हिस्सा 28.26% है।

विगत पांच वर्ष (2020-21 से 2024-25) के दौरान, देश में कुल 86.00 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई है, जिसमें 70.04 गीगावाट सोलर उर्जा, 12.29 गीगावाट पवन उर्जा, 1.36 गीगावाट बायो-पावर और 2.31 गीगावाट पन उर्जा की क्षमता शामिल है।

दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 259.42 गीगावाट और 250.64 गीगावाट है, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता 505.02 गीगावाट का क्रमशः 51.37% और 49.63% है।

(ख) से (ड़) सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसीज) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करती हैं। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2024-25 में 1000 करोड़ लीटर से ज़्यादा हो गया है, जिससे ईएसवाई 2024-25 के दौरान पेट्रोल में औसतन 19.24% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया गया है। माह अक्टूबर, 2025 के दौरान, 19.97% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य हासिल किया गया है।

ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से अक्टूबर 2025 तक किसानों को 1,36,300 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ है, इसके अलावा 1,55,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, लगभग 790 लाख मीट्रिक टन शुद्ध सीओ2 में कमी आई है और 260 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।

*****